श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश): महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से मैं भी अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

कुछ माननीय सदस्य: महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से हम भी अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Parliamentary Affairs Minister is here. Mr. Naqvi, this is an important issue. Some teachers are not being paid the Government pay scale, which is discrimination. So, please report it to the Minister for Human Resource Development and come back.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): Okay, Sir.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Import duty on wheat

*376. SHRI HARIVANSH: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government has any plan of hiking import duty on wheat so that wheat prices do not crash in the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, what steps have been proposed to be taken to protect the interests of farmers?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RADHA MOHAN SINGH): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Government has raised import duty on wheat from zero to 10 % with effect from 28th March, 2017.

(c) To check decline in prices and ensure stability in domestic market, several steps are taken by the Government such as fixing Minimum Support Price (MSP) every year and procurement of wheat from the farmers.

श्री हरिवंशः सभापति जी, आपके माध्यम से मेरा पहला सप्लीमेंटरी सवाल है कि अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने सही कहा है कि गेहूं पर 28 मार्च, 2017 से दस फीसदी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, इसके बाद भी बाहर से आने वाला गेहूं सस्ता है। मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की 31 मार्च, 2017 की खबर को क्वोट कर रहा हूं। "Millers in South India say that they will continue importing wheat from Australia and Black Sea region, even with a ten per cent duty imposed this week, as it is cheaper than locally grown supply." स्पष्ट है कि इस प्रकार के कदम के बावजूद भारतीय किसानों को भारी नुक़सान हो रहा है, इसलिए किसान संघों की मांग है कि सितम्बर, 2016 में गेहूं पर इम्पोर्ट ड्यूटी को 25 फीसदी से घटाकर ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप सवाल पूछिए।

श्री हरिवंशः सर, मेरा यह सवाल है कि उनकी मांग है कि दिसम्बर, 2016 में गेहूं पर इम्पोर्ट ड्यूटी 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी की गई, उसके बाद पुनः दिसम्बर, 2016 में इम्पोर्ट ड्यूटी 10 फीसदी से घटाकर 0 फीसदी की गई, इसलिए बाहर से आने वाले गेहूं पर न्यूनतम इम्पोर्ट ड्यूटी 25 परसेंट हो, यह किसानों की मांग है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसानों की इस मांग पर विचार कर रही है?

श्री राधा मोहन सिंहः सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार के आने से पहले गेहूं पर कभी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगी थी। यह ड्यूटी पहली बार हमारी सरकार ने लगाई थी। उसके बाद, पिछले वर्ष ऐसा अनुमान आया था कि इसमें कुछ कमी हो सकती है, इसलिए उसको समाप्त किया गया था और फिर 10 प्रतिशत लगाई गई थी। मैं कोशिश करूंगा कि यह और अधिक बढ़ सके, तो मैं इसके लिए प्रयास भी करूंगा, लेकिन यह पहले नहीं लगती थी, यह इसी सरकार के आने के बाद लगी, फिर हटी और अभी 10 प्रतिशत लगाई गई है, ताकि बाहर से गेहूं आना कम हो।

श्री हरिवंशः महोदय, आपके माध्यम से मेरा दूसरी सप्लीमेंटरी सवाल माननीय कृषि मंत्री जी से है कि आप किसानों को जब डीजल, पेट्रोल बेचते हैं तो उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बजार के मानक मूल्यों के तहत तय करते हैं। जब आप अन्य उत्पाद खरीदते हैं, तो उसका मूल्य बाजार के अनुरूप क्यों नहीं तय करते हैं? यह भेदभाव क्यो हैं? मैंने कभी आरोप नहीं लगाया, आपने लगाया था। मैंने कहा कि आपने घटाया, बाद में 25 से 10 किया, फिर ज़ीरो किया। आप उसको वहीं पर रखते, जिससे किसानों को फायदा होता।

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, जहां तक समर्थन मूल्य का सवाल है, जो 22 जिंसों का है, उसकी एक प्रक्रिया है और उसको रिव्यू करने के लिए एक कमेटी भी बनी है और उसकी रिपोर्ट भी आई है। जो दूसरा विषय माननीय सदस्य का है, तो मैं कहना चाहूंगा कि और भी अन्य योजनाएं हैं समर्थन मूल्य के अलावा, 22 जिंसों का समर्थन मूल्य तय है, जिनका समर्थन मूल्य तय नहीं है, उसका उत्पादन किसी राज्य में 10 प्रतिशत ज्यादा होता है और 10 प्रतिशत से नीचे आ जाता है तो हमारी जो एक योजना है, उसके तहत राज्यों से प्रस्ताव आता है।

श्री हरिवंशः सर, सवाल कुछ और है और जवाब कुछ और है।

श्री सभापतिः आप सुन लीजिए।

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, सब का समर्थन मूल्य नहीं है। समर्थन मूल्य सिर्फ 22 जिंसों का है। जिनका समर्थन मूल्य नहीं है उसके विषय में बतला रहा हूं। कई राज्यों ने इस योजना का लाभ उठाया है और इसको राज्यों के सहयोग से करवाते हैं और आधी राशि भारत सरकार और आधी राशि राज्य सरकार देती है। कई राज्यों ने इस योजना का लाभ उठाया है।

श्री शरद यादवः सभापति जी, सम्माननीय सदस्य श्री हरिवंश जी ने जो पूछा है उसका जवाब नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से नये सिरे से उनसे जवाब पूछना चाहता हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दुनिया भर में व्हीट की बम्पर क्रॉप आई हुई है। मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि यह जीरो इंपोर्ट ड्यूटी की गई थी, जरा खोज करिए। यहां अनाज के बहुत दलाल घूमते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, आपने 10 फीसदी किया है। माननीय सदस्य हरिवंश जी ने पूछा है कि इसको बढ़ा करके 25 फीसदी करिए। मेरा पहला सवाल तो यह है। दूसरी बात, जो दाल है, इस सरकार के प्रयास से और आपके प्रयास से, इसकी बम्पर ड्रॉप हुई है, उसका भी इम्पोर्ट चल रहा है। यह बहुत सारा, हजारों-लाखों टन पड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से इनसे यह कहना चाहता हूँ कि दाल पर और गेहूँ पर आपने जो पहले 25 प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई थी, उसको लगाइए। दुनिया के बाजारों में गेहूँ बहुत पैदा हुआ है और यह जो 10 फीसदी लगाया गया है, इससे काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही, आप दाल पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने का काम कीजिए। यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ।

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, जहां तक दाल का सवाल है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से अपने देश में इस बार दाल का उत्पादन बम्पर होने की उम्मीद है। लेकिन फिर भी, जितनी हमारी जरूरत है, उतना हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी, तूर पर आयात शुल्क को हमने बढ़ाया है और अपने देश के अन्दर लगभग 6 राज्यों में किसानों से तूर की हमारी खरीदारी जारी है, जो 15 अप्रैल तक चलेगी।

जहां तक गेहूँ का सवाल है, मैंने पहले ही बताया कि पहली बार हमारी सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई थी। इसके पहले यह कभी लगी ही नहीं। इसे तब ज़ीरो पर लाया गया, जब यह सम्भावना आई कि गेहूँ की कमी है, जो आंकड़े आए थे और फिर जो बाकी अर्थशास्त्रियों ने बताया। जो आंकड़े आए, उनको देखते हुए, यह महँगा नहीं हो, इसलिए उसको ज़ीरो किया गया था। लेकिन फिर भी, उत्पादन अच्छा हो रहा है, तो इसे अभी 10 प्रतिशत किया गया है।

श्री सभापतिः श्री जयराम रमेश। ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादवः सर ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः नहीं, नहीं, शरद जी..

श्री शरद यादवः सर, मेरी एक बात तो सुनिए। सर, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी जो कह रहे हैं, मैंने इम्पोर्ट ड्यूटी के बारे में यह पूछा है। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूँ का दाम बहुत नीचे है, किसी आदमी ने इम्पोर्ट ड्यूटी ज़ीरो परसेंट की है, उस पर भी आपको जांच करनी चाहिए कि किसने यह किया है? आपने यह नहीं किया है।

श्री सभापतिः थैंक यू।

श्री शरद यादवः इन्होंने किया है। ...(**व्यवधान**)... तो सवाल यह है कि इसे आप 25 परसेंट करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री राधा मोहन सिंहः सर, इसकी एक प्रक्रिया है। इसे सीधे मेरा मंत्रालय नहीं करता है। अभी दो-तीन मंत्रालयों ने मिल कर यह जो किया है, 10 प्रतिशत किया है। मैं आपको फिर यही कहूँगा कि यह कभी लगता ही नहीं था, इस सरकार के आने के बाद इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की हमने शुरुआत की है, ताकि बाहर से यह कम आये। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः ठीक है। श्री जयराम रमेश।

SHRI JAIRAM RAMESH: Thank you, Mr. Chairman, Sir. Sir, my question flows from part (c) of the Minister's answer to this question. Sir, on the 10th of March to Rajya Sabha Starred Question No. 115, the hon. Minister gave an answer, which said that the cost of production of wheat is ₹ 797 per quintal. The MSP for wheat in 2016-17 is ₹ 1,625 per quintal which means that return on cost is 103 per cent. This is an answer given by the hon. Minister on the 10th of March in response to a question by Dr. Jatiya. Sir, my question is this. Number one, does this mean that Swaminathan Committee Report recommendation of a 50 per cent return on cost has automatically been implemented? Secondly, Sir, I have checked this number with U.P., with Punjab, with Bihar and with other wheat-growing States. Nobody believes that the cost of production of wheat is less than ₹ 800 a quintal. Most people believe that the cost of production is anywhere between ₹ 2,500 and ₹ 3,000 per quintal. I would like to ask the Hon. Minister whether he will review the cost of production of wheat because it is on that the MSP is determined. Unless you review the cost of production, you are not going to get a remunerative price for wheat farmers.

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, यह जो समर्थन मूल्य है— जो मूल्य एवं लागत आयोग है, 16 राज्यों के अन्दर विश्वविद्यालयों के माध्यम से इसके जो नॉर्म्स हैं, उनके तहत लागत मूल्य और उसके आधार पर समर्थन मूल्य तय करते हुए अपने राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखते हुए वह लागत मूल्य तय करता है। मैंने यह भी बताया था कि एक कमेटी बनी और उसने कुछ रिपोर्ट्स दी हैं। इसे जो तय करने की प्रक्रिया है, उस पर कुछ सुझाव आए हैं कि इसमें थोड़ा बदलाव हो, तय करने का जो तरीका है, उस पर थोड़ा विचार किया जाए। उस पर मंत्रालय विचार कर रहा है। एक प्रक्रिया पहले से चल रही है। एक कमेटी के सुझाव आये हैं, उनको मंत्रालय देख रहा है।

सरदार बलविंदर सिंह भंडरः ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं माननीय मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूँ कि सभी मेम्बर्स, सभी पार्टीज़ के मेम्बर्स, कोई भी सैटिस्फाइड नहीं है कि व्हीट की जो प्राइस फिक्स की जाती है, वह जायज़ है। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसको आप छोड़िए, आप यह देखिए कि आज suicides क्यों हो रही हैं? उसका कारण यह है कि जो प्राइस है, वह ठीक नहीं मिलता है। मैं यह मांग करता हूँ कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, उसको दोबारा 25 परसेंट किया जाए और आगे के लिए एक लांग टर्म पॉलिसी बनाई जाए ताकि पांच-सात साल

तक कभी इम्पोर्ट नहीं किया जाए। पिछले साल 25 लाख टन, फिर 50 लाख टन इम्पोर्ट किया गया, जब कि हमारे पास बफर स्टॉक है।

सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई लांग टर्म पॉलिसी बनाई जाएगी? इसके साथ ही मेरी यह भी राय है कि आप किसानों को उनकी पैदावार की सही कीमत दीजिए, तभी किसान बचेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो suicides नहीं रुकेंगी।

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, समर्थन मूल्य तय करने की जो प्रक्रिया है, उस पर कमेटी के जो सुझाव आए हैं, उनको हम दिखवा रहे हैं, लेकिन किसानों की आमदनी बढ़ने के सवाल पहले भी आए हैं, इसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सिर्फ समर्थन मूल्य बढ़ने से ही आमदनी नहीं बढ़ सकती है, बल्कि समर्थन मूल्य भी उसमें एक सप्लीमेंटरी कारक है। आज देश में हर खेत को पानी नहीं है, पानी भी तो मिलने की व्यवस्था करनी चाहिए, फिर उच्च पैदावार क्वालिटी के बीज और planting materials मिले, फिर लागत कम हो, मूल्य अच्छा मिले, इसके लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं... इसी सदन में सब लोगों ने कई बार भाषण किया है कि एक सौ बड़ी और मध्यम श्रेणी की परियोजनाएं 30 वर्षों से लंबित हैं, जिनसे 76 लाख हेक्टयर भूमि की सिंचाई हो सकती है। इनमें 80 हजार करोड़ रुपए का खर्च था, वह 25-30 वर्षों से नहीं हो सका। पहली बार इस सरकार ने 40 हजार करोड़ रुपए का corpus fund बनाया। 2015-16 में 23 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों को पैसा दिया गया है और चार साल में इस काम को करना है।

इसी तरह से 'राष्ट्रीय कृषि मंडी' बनाई गई, कई राज्य बड़ी तेजी के साथ इसमें लगे हैं और अभी तक लगभग 300 से ज्यादा मंडियां इससे जुड़ चुकी हैं, जिससे उनको अच्छी कीमत मिलती है।

तीसरी बात यह है कि देश में किसानों की सुविधाओं के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, पहले से भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जब आप इनके 7-8 वर्षों के आंकड़े देखेंगे, तो पता चलेगा कि यदि किसी राज्य को किसी मद में 200 करोड़ रुपए मिले, तो उस वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए, फिर दूसरे वर्ष उसको 200 करोड़ रुपए मिलने थे, तो पहले के 100 करोड़ रुपए कम हो गए। इस तरह से 10 वर्षों का आंकड़ा देखें... हम इस बार यह जारी करने वाले हैं कि किस राज्य में पिछले 8-10 वर्षों के अंदर किसानों के हित की योजनाओं के लिए कितना पैसा गया। हम सब इस काम के लिए चिंतित हैं, लेकिन जितनी चिंता हम यहां करते हैं, यदि राज्यों के अंदर भी इसकी चिंता की जाए, तो इससे किसान का बड़ा भला होगा।

Strengthening cold storage and warehousing Infrastructure in Andhra Pradesh

*377. SHRI T. G. VENKATESH: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government is planning to strengthen cold storage and warehousing infrastructure facilities in Andhra Pradesh, if so, the details thereof; and